मैसर्स बीएचएस उद्योग

बनाम

निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2729/2009)

7 जुलाई 2015

[दीपक मिश्रा एवं वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

अनुबंध - बीमा का अनुबंध - निर्यातक स्वामित्व वाले संस्थान और निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम के बीच – नौ परिवहन व्यापक जोखिम पालिसी जारी - निर्यातक द्वारा भेजे गए माल की खेपें जो बीमा द्वारा संरक्षित थीं और जो बीमा द्वारा संरक्षित नहीं थीं – -

बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता-निगम को अस्वीकृति की सूचना और बीमा के माध्यम से संरक्षित नहीं किए गए नौ परिवहन के बारे में सूचना - बीमा दावा - बीमाकर्ता द्वारा यह कहते हुए खारिज किया गया कि बीमाधारक ने पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया। अभिनिर्धारितः पालिसी के अनुच्छेद 5 के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता कि बीमाधारक ने भुगतान की अवधि में कमी के संबंध में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था - हालांकि, बीमाधारक ने नौ परिवहन की घोषणा की शर्त को छोड़ दिया, जो संख्या में 50% और मूल्य में 30% तक थी, जो कि पालिसी के अनुच्छेद 1, 2, 7(ए), 8(ए), 10, 19(ए), 28 और 29 का उल्लंघन था - इसलिए, पालिसी का संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से निर्माण करने के बाद, बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं थोपा जा सकता - बीमाकर्ता ने दावे को सही तरीके से खारिज किया।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. यदि पालिसी के अनुच्छेद 5(सी) को सही ढंग से समझा जाए, तो मौजूदा तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में, यह नहीं कहा जा सकता कि भुगतान की अवधि में कमी के संबंध में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जो निर्धारित किया गया है वह यह है कि यदि बीमाधारक 180 दिनों से अधिक समय के लिए उधार देता है, तो निगम दायित्व से मुक्त होगा। वह अधिकतम सीमा है। 2.9.1999 के पत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने नौ परिवहन के 90 दिनों के भीतर भुगतान की शर्तें दिखाई हैं। अपीलार्थी ने 60 दिनों का उधार दिया था जो कि 90 दिनों की अधिकतम सीमा के भीतर है। इस प्रकार, चूंकि बीमाधारक ने उक्त अवधि के भीतर कर्ज निर्धारित किया है, इसलिए उसे उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता। [पैरा 23] [386-जी-एच; 387-ए-बी]

2.1 पालिसी के शर्तों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि यदि अस्पष्टता हो, तो अर्थान्वयन बीमाधारक के पक्ष में किया जाना चाहिए। पालिसी के अनुच्छेद 8(अ) और 19(अ) घोषणाओं और दायित्व से छूट के संबंध में व्यवहार करते हैं। ये पूरी तरह से विशिष्ट हैं और उनमें निर्धारित अनुसार, बीमाधारक पर पालिसी के अंतर्गत एक दायित्व डाला गया है। उसे पालिसी के अंतर्गत निगम को प्रत्येक कैलेंडर माह के 15 वें दिन या उससे पहले प्रारूपित प्रारूप में सभी नौ परिवहनों का विवरण देने के लिए बाध्य किया गया है, जो पिछले माह के दौरान किए गए हैं और यहां तक कि अगर कोई नौ परिवहन नहीं किया गया है तो 'शून्य' घोषणा देनी आवश्यक है। अनुच्छेद 19(अ) अनुच्छेद 8(अ) के अनुसार घोषणा का उल्लेख करता है। इसमें 'बिना किसी व्यतिक्रम के' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यह अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रीमियम के भुगतान से संबंधित एक और पूर्वानुमान जोड़ता है। अनुच्छेद 19(अ) में दोहरी आवश्यकताओं का निर्धारण संचयी है। इन्हें पृथक रूप में पढ़ा नहीं जा सकता। बीमाधारक को अनुच्छेद 8(अ) के अनुसार

बिना चूक के नौ परिवहन की घोषणा करनी होती है और साथ ही अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। केवल प्रीमियम का भुगतान करना निगम को हानि की प्रतिपूर्ति करने या उस पर दायित्व थोपने के लिए पर्याप्त नहीं है। दावे को बनाए रखने के लिए बीमाधारक की ओर से यह भी आवश्यक है कि दिखाया जाए कि घोषणा के संबंध में अनुपालन हुआ है। अनुच्छेद 8(अ) की व्याख्या यह कहने के लिए कि बीमाधारक के पास विकल्प है कि वह किस नौ परिवहन को कवर करेगा और किन्हें छोड़ देगा, पालिसी के आदेश के विरुद्ध जाएगी। [पैरा 27] [390-जी,एच; 391-ए-एफ]

2.2 सामान्य अनुच्छेद मुख्य रूप से यह बताते हैं कि कौन से जोखिम संरक्षित हैं और कौन से नहीं हैं, प्रीमियम कैसे गणना किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। जो अंततः मायने रखता है वह है जहाँ बीमाकर्ता की दायित्व स्पष्ट रूप से बहिष्कृत है, पालिसी के उक्त अनुच्छेद पूरी तरह से स्पष्ट, एकरूप और अस्पष्टता रहित हैं। वाणिज्यिक लेन-देन में एक पालिसी प्राप्त करने के बाद बीमाधारक को पूरी पालिसी को समझना होता है। पालिसी का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से निर्माण करने से यह स्पष्ट है कि कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है जो बीमाधारक-अपीलार्थी के पक्ष में व्याख्या की आवश्यकता को जन्म दे। अपीलार्थी ने अनुच्छेद 8(अ) में निर्धारित अनुसार घोषित नहीं किया है, इस प्रकार ऐसी प्रकृति के बीमा अनुबंध की व्याख्या की अवधारणा के लिए यह विपरीत होगा, यदि बीमाकर्ता पर दायित्व थोपा जाता है। [पैरा 27] [391-जी-एच; 392-ए-सी]

एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य **2004 (3) एससीसी 553**; कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **1990 (1) सप्ल. एससीआर 625: 1991 (1) एससीसी 212- प्रतिष्ठित।**

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोनी चेरियन **1999 (1) सप्ल एससीआर 622: 1999 (6) एससीसी 451;** पॉलिमर इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य **2004 (6) सप्ल एससीआर 535**: **2005 (9) एससीसी 174**; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम.के.जे. निगम. **1996 (5) सप्ल एससीआर 20: 1996 (6) एससीसी 428;** समामेलित विद्युत कंपनी बनाम अजमेर नगर पालिका **(1969) 2 एससीआर 430: एआईआर 1969 एससी 227**; बे बेरी अपार्टमेंट्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम शोभा और अन्य **2006 (7) सप्ल।** एससीआर **738: 2006 (13) एससीसी 737**; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल **2004 (4) सप्ल। एससीआर 662: 2004 (8) एससीसी 644;** जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदमुल जैन **(1966) 3 एससीआर 500**: एआईआर **1966 एससी 1644;** राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम पी. पी. सिंह 2003 (1) एससीआर 593: 2003 (4) एससीसी 239; मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बा/वंत राव चव्हाण 1989 (2) एससीआर 454: 1989 (3) एससीसी 132; बाबू वर्गीस बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल 1999 (1) एससीआर 1121: 1999 (3) एससीसी 422 - संदर्भित।

बाज (रन ऑफ) लिमिटेड बनाम डरहम और अन्य (2012) यूकेएससी 14-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1996 (5) पूरक एससीआर 20 का उल्लेख किया गया	पैरा 9
(1969) 2 एससीआर 430 संदर्भित	पैरा 10
2006 (7) पूरक एससीआर 738 का उल्लेख किया गया	पैरा 11
2004 (6) पूरक एससीआर 535 का उल्लेख किया गया	पैरा 12, 25
(1966) 3 एससीआर 500 का उल्लेख किया गया	पैरा 13, 25

(2012) यूकेएससी 14 का उल्लेख किया गया पैरा 14

2003 (1) एससीआर 593 संदर्भित पैरा 15

1989 (2) एससीआर 454 संदर्भित पैरा 15

1999 (1) एससीआर 1121 का उल्लेख पैरा 15

2004 (4) पूरक एससीआर 662 का उल्लेख किया गया पैरा 16

1999 (1) पूरक एससीआर 622 का उल्लेख किया गया पैरा 17

2004 (3) एससीसी 553 विशिष्ट पैरा 28

1990 (1) पूरक। एससीआर 625 विशिष्ट पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2729/2009

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रथम अपील संख्या 189/2007 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.08.2007 से उत्पन्न।

निदेश गुप्ता, तरूण गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से।

भरत संगल, सृजना लामा, आई. अबेनला एइर, अनसूया चौधरी, प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति

1. विशेष अनुमति द्वारा, यह वर्तमान अपील, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में 'आयोग') द्वारा 20.08.2007 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें प्रथम अपील संख्या 189/2007 में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'राज्य आयोग') द्वारा 15.2.2007 को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है, जहाँ राज्य आयोग ने

शिकायत मामला संख्या 82/2002 (पंजाब)/RBT संख्या 46/2006 में शिकायतकर्ता-अपीलार्थी के दावे को दो कारणों से खारिज किया था, अर्थात्, दावा समय सीमा द्वारा बाधित था, और पालिसी के अंतर्गत यह पूरी तरह से अस्थिर था।

2. इंगित करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अपीलार्थी, जो कि एक लघु उद्योग और हस्तशिल्प वस्तुओं में सौदा करने वाला स्वामित्व वाला संस्थान है, अपने माल को मैसर्स ट्रेजर्स ऑफ इंडिया, अटलांटा, यूएसए को निर्यात करने की इच्छा से, पहले प्रतिवादी से 15.6.1999 को बीमा संरक्षण लिया और उसी तारीख को अपीलार्थी को एक नौ परिवहन व्यापक जोखिम पालिसी जारी की गई। पालिसी के तहत प्रतिवादी-बीमाकर्ता की अधिकतम दायित्व सीमा 30 लाख रुपए थी। बीमाकर्ता ने प्रारंभ में मैसर्स ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के लिए 14.7.1999 को 8 लाख रुपए की अस्थायी क्रेडिट सीमा प्रदान की थी, जिसे 20.7.1999 को 10 लाख रुपए और बाद में 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। अपीलार्थी ने 15.7.1999 को मैसर्स ट्रेजर्स ऑफ इंडिया को 6,50,000/- रुपए की एक खेप भेजी थी और इसके संबंध में प्रतिवादियों को उचित घोषणा भेजी गई थी। ध्यान दें, अपीलार्थी ने नरिमन पॉइंट, मुंबई स्थित एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड को उसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से और उसी निगम को सूर्यकांत कॉम्प्लेक्स, लुधियाना के उसके शाखा प्रबंधक के माध्यम से क्रमशः प्रतिवादी 1 और 2 के रूप में शामिल किया है। जैसा कि दावा किया गया है, अपीलार्थी ने उपरोक्त खरीददार से आगे के आदेश प्राप्त किए थे और खेपों को तुरंत भेजा जाना था। अपीलार्थी ने उक्त खरीददार के संबंध में अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति के लिए प्रतिवादियों को लिखते रहे। 20.8.19.99 को अपीलार्थी ने उक्त खरीददार को और 4,76,139/- रुपए की एक और खेप भेजी और इसके संबंध में प्रतिवादियों को घोषणा भी भेजी गई। अपीलार्थी को खरीददार से और आदेश प्राप्त हुए, परंतु निगम ने अतिरिक्त क्रेडिट के लिए अनुमोदन नहीं दिया था। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी ने 20.8.1999

को कुल मिलाकर 2,77,732/- और 1,00,512/- रुपए की दो खेपें भेजीं। अपीलार्थी का यह मामला है कि उक्त दो खेपें उसके अपने जोखिम पर भेजी गईं थीं क्योंकि निगम ने मांगी गई अतिरिक्त सीमा को स्वीकृत नहीं किया था। इस स्थिति में, 29.9.1999 को अपीलार्थी को उसके बैंक द्वारा सूचित किया गया कि खरीददार ने 15.7.1999 और 20.8.1999 की तारीखों वाले चालानों के संबंध में भेजी गई खेपों के लिए ड्रॉई बैंक अर्थात सन ट्रस्ट अटलांटा, यूएसए के साथ नेगोशिएट किए गए दस्तावेज़ों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और इसलिए दस्तावेज़ वापस भेज दिए गए थे। चूंकि खरीददार ने भारत से पहले ही निर्यात किए गए माल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए 22.10.1999 को अपीलार्थी ने निगम को खरीददार द्वारा दस्तावेज़ों की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी ने 10.12.1999 के पत्र द्वारा बीमा के माध्यम से संरक्षित नहीं की गई खेप के बारे में भी प्रतिवादी-निगम को सूचित किया।

3. जैसा कि तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य आगे खुलता है, 22.12.1999 को निगम ने एक संचार भेजा जिसमें यह बताया गया कि स्वीकृत सीमा 20 लाख रुपए थी, और उसने अपीलार्थी से निर्धारित प्रारूप पर औपचारिकताओं का पालन करने को कहा। 11.1.2000 को, निगम ने अपीलार्थी से भुगतान न होने का कारण पूछा और खरीददार के साथ संभावनाओं का पता लगाने और आगे बातचीत करने और कदम उठाने के लिए कहा। इसके बाद, अपीलार्थी ने उपरोक्त दावे के भुगतान के लिए एक पत्र भेजा और चूंकि उक्त संचार का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने दावे को शीघ्रता से संसाधित करने के लिए स्मरण पत्र भेजे। प्रतिवादियों ने 6.6.2000 को उक्त पत्रों के जवाब में दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निगम की दायित्व अनिवार्य व्यतिक्रमों की एक श्रृंखला के कारण आकर्षित नहीं हुई थी।

4. उपरोक्त संचार से आहत होकर, अपीलार्थी ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य आयोग का रुख किया। हालांकि दो अपीलें दायर की गईं, राज्य आयोग ने

उन्हें एक अपील के रूप में माना। राज्य आयोग के समक्ष प्रतिवादियों ने दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं, कि शिकायत समय सीमा द्वारा बाधित थी, और यह अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी। राज्य आयोग ने, तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन करते हुए यह निर्णय लिया कि शिकायत एक उचित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी लेकिन यह समय सीमा द्वारा बाधित थी। हालांकि, राज्य आयोग ने मामले को गुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हुए इस संबंध में निर्णय लिया कि:-

> "27. 20.8.99 को चालान संख्या 006 के माध्यम से की गई 4,76,139/- रुपए की खेप, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-13 है, विचार में नहीं ली जा सकती क्योंकि शिकायतकर्ता ने भुगतान की शर्तों में परिवर्तन किया था, जो कि 60 दिनों के डी.ए. अर्थात वितरण के 60 दिनों के बाद भुगतान के रूप में उल्लेखित किया गया था, जबकि अनुलग्नक पी-9 में इसे 90 दिनों के डी.ए. के रूप में उल्लेखित किया गया है अर्थात नौ परिवहन की तारीख से 60 दिनों के बजाए 90 दिनों के भीतर दस्तावेज़ों की स्वीकृति पर भुगतान। बीमा पालिसी में शर्तों और प्रावधानों के तहत यह कहा गया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-4 के अंतर्गत 'सामान्य' शीर्षक में शर्तें 28 और 29 में है कि यहां निहित प्रत्येक शर्त और प्रावधान का उचित प्रदर्शन और पालन निगम की यहां के तहत किसी भी दायित्व के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होगी और यदि बीमाधारक शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो पालिसी को माना जाएगा कि इसे त्याग दिया गया है। चूंकि, शिकायतकर्ता 20.8.99 को दूसरी खेप के लिए 4,76,139/- रुपए की 90 दिनों के डी.ए. शर्त का पालन करने में विफल रहा, जैसा कि भुगतान की शर्त को 90 दिनों के डी.ए. के बजाय 60 दिनों के डी.ए. में बदल दिया गया था, इसलिए, प्रतिवादी को इस राशि का भुगतान करने से मुक्त कर दिया गया।

28. शिकायतकर्ता का आगे का मामला यह है कि खरीददार ने दस्तावेज़ों को निवृत्त नहीं किया और माल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिस कारण दस्तावेज़ पंजाब एंड सिंध बैंक को वापस कर दिए गए। यह ज्ञात नहीं है कि 15.7.99 को चालान संख्या 005 के माध्यम से या 20.8.99 के चालान संख्या 006 के माध्यम से भेजे गए माल का क्या हुआ। अनुलग्नक पी-35 में यह कहा गया है कि माल बंधक गोदाम में पड़ा था। यह ज्ञात नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उन मालों को बेचने और कुछ पैसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए। बिलों को नोटरी के माध्यम से 'नोटेड और प्रोटेस्टेड' नहीं करवाया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि ड्रॉई के बैंक ने दस्तावेज़ों को 'नोटेड और प्रोटेस्टेड' करवाने से इनकार कर दिया था। यदि शिकायतकर्ता ने कुछ कदम उठाए होते तो शायद माल पुनः प्राप्त हो जाते या नीलाम किए जा सकते थे और कुछ पैसे मिल सकते थे, लेकिन शिकायतकर्ता ने भेजे गए माल के लिए प्रतिवादी के भुगतान करने के बंधन को मानते हुए उनकी चिंता नहीं की। यह साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता ने यूएसए में ऋण संग्रह एजेंसी को कोई पत्र लिखा था। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने माल की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए और इसलिए राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। शिकायतकर्ता को लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर माल की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ड्रॉई के बैंक सन ट्रस्ट इंटरनेशनल अटलांटा, यूएसए से कोई पत्र नहीं है कि उसने दस्तावेज़ों को 'नोटेड और प्रोटेस्टेड' किया था। माल को वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। निश्चित रूप से शिकायतकर्ता का कार्य पालिसी की शर्तों और प्रावधानों के विरुद्ध है और इस प्रकार दावा की गई राशि का हकदार नहीं है।"

5. राज्य आयोग के समक्ष असफलता के कारण अपीलार्थी को आयोग के समक्ष पर्थम अपील दायर करने की मजबूरी हुई, जिसने राज्य आयोग के इस निष्कर्ष से सहमति नहीं जताई कि शिकायत परिसीमा बाधित थी। हालांकि, आयोग ने पालिसी की शर्तों और प्रावधानों, विशेष रूप से शर्त संख्या 28, 29, पालिसी के बहिष्करण खंड संख्या 7 का उल्लेख किया, अपीलार्थी के 15.1.2000 और 18.1.2000 के पत्रों के जवाब में प्रतिवादी द्वारा 26.1.2000 को भेजे गए संचार का संदर्भ लिया, दावे के खंडन के संचार पर जोर दिया, भुगतान की शर्तों से संबंधित एकतरफा शर्तों और प्रावधानों में परिवर्तन, अपीलार्थी द्वारा माल की पुनर्प्राप्ति के लिए कदम न उठाने पर बल दिया और तदनुसार राय व्यक्त की कि पालिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था और अपीलार्थी नौ परिवहन की रक्षा करने के लिए सतर्क नहीं रहा था। इस दृष्टिकोण के साथ, उसने अपील खारिज कर दी।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता और प्रतिवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत संगल को सुना।

7. तथ्यों की बारीकी से जांच पर, यह स्पष्ट है कि 15.7.1999 को मैसर्स ट्रेजर्स ऑफ इंडिया को 6,50,000/- रुपए की एक खेप भेजी गई थी और इसके संबंध में प्रतिवादियों को घोषणा भी संचारित की गई थी। इसी प्रकार, 20.8.1999 को, अपीलार्थी ने उसी खरीददार यानी मैसर्स ट्रेजर्स ऑफ इंडिया को एक और खेप 4,76,139/- रुपए की भेजी और घोषणा निगम को भेजी गई। यह भी निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने 20.8.1999 को 2,77,732/- और 1,00,512/- रुपए की दो खेपें भेजीं। अपीलार्थी का तर्क है कि चूंकि पहले दो लेन-देन ने 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा को कवर किया था और निगम अतिरिक्त सीमा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब कर रहा था, इसलिए बाद की दो खेपें अपीलार्थी के जोखिम पर भेजी गईं थीं। चूंकि खरीददार ने माल स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए अपीलार्थी ने 22.10.1999 को निगम को

इसके बारे में सूचित किया और 10.12.1999 को बीमा के तहत संरक्षित नहीं की गई खेपों के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी का दावा है कि निगम ने 22.12.1999 को संचारित किया कि स्वीकृत सीमा 20 लाख रुपए थी और अपीलार्थी से निर्धारित प्रारूप पर सूचित करने को कहा, जिसका अपीलार्थी ने ठीक से पालन किया, लेकिन इसके बावजूद, निगम ने 6.6.2000 के पत्र द्वारा अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। बीमाकर्ता द्वारा संचारित का संबंधित भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "1. आर्डर फॉर्म में भुगतान की शर्तें DA-90 दिनों के रूप में समुद्री मार्ग से उल्लेखित हैं, लेकिन आपने 4,76,139/- रुपए की खेप को वायु मार्ग से DA-60 दिनों पर प्रभावित किया। जहां तक 6,50,000/- रुपए की खेप का संबंध है, जिसे DA-90 दिनों पर प्रभावित किया गया है, इनवॉयस में भुगतान की शर्तों को DA-90 दिनों के रूप में दिखाया गया है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज DA-60 दिनों के आधार पर तैयार किया गया था। इसे आपकी ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में समझा जाता है।
>
> 2. आपने संख्या में 50% और मूल्य में 34% की खेपों की घोषणा करने में चूक की है। इसे गंभीर और निंदनीय चूक माना जाता है, जो पालिसी शर्तों के अनुच्छेद संख्या 1,2,8(अ) 10, 19(1), 28, 7(अ) और 29 का उल्लंघन करता है।
>
> 3. बिल को खरीददार के देश में नोटेड और प्रोटेस्टेड नहीं किया गया था।"

8. मामले का सार यह है कि क्या बीमाकर्ता द्वारा खंडन के लिए आरोपित कारणों की जांच सहन कर सकते हैं। श्री निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें कुछ द्रष्टांतों की ओर निर्देशित किया है, जो, उनके अनुसार, तब प्रासंगिक होते हैं जब एक

न्यायालय को बीमा पालिसी की व्याख्या करनी आवश्यक होती है। हम पहले उन द्रष्टांतों का उल्लेख करेंगे और उसके बाद वहां निहित अनुपात के पृष्ठभूमि में बीमा पालिसी के विभिन्न अनुच्छेदों की जांच करेंगे और इस मुद्दे के संबंध में हमारे विचार व्यक्त करेंगे कि क्या वे इस मामले में लागू होते हैं और यदि हां, तो क्या ऐसी लागूता अपीलार्थी के दावे को ध्वस्त कर देगी।

9. प्रारंभ में, यह कहा जा सकता है कि बीमा के अनुबंध उच्चतम विश्वास के अनुबंध हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करना आवश्यक है। 'यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. बनाम एम.के.जे. कॉर्पोरेशन'[1] मामले में दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने टिप्पणी की है:-

> "बीमा कानून का एक मौलिक सिद्धांत यह है कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा उच्चतम स्पस्ट पालिसी का पालन किया जाना चाहिए। स्पस्ट पालिसी दोनों पक्षों को ऐसे तथ्य को छिपाने से रोकती है (गैर-खुलासा) जो वे निजी रूप से जानते हैं, ताकि दूसरे को उस तथ्य की अज्ञानता और इसके विपरीत विश्वास करने से सौदे में ध्यानाकर्षित किया जा सके। जैसे बीमाधारक का खुलासा करने का कर्तव्य है, इसी तरह बीमाकर्ताओं और उनके एजेंटों का भी उनके ज्ञान में आने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने का कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी पालिसी का दायित्व उन पर बीमाधारक के समान रूप से लागू होता है"

इन सिद्धांतों के संबंध में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत द्रष्टांतों को देखा जाना है।

10. अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाम अजमेर नगर पालिका[2] मामले में, हालांकि एक अलग संदर्भ में, यह माना गया है कि: -

"पक्षों के बीच हुए अनुबंध की सही प्रकृति की व्याख्या करते समय, अनुबंध को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और यदि इसे इस प्रकार पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट है कि जो कुछ वादी ने किया था वह कुएँ से पानी पंप करना था और किसी भी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति नहीं थी। इसलिए हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों की इस संबंध में वादी के मामले को असफल मानने की राय से सहमत हैं।"

11. बे बेरी अपार्टमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम शोभा और अन्य[3] मामले में, न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय, न्यायालय किसी अन्य अर्थ को आवंटित नहीं कर सकता; और जैसा कि अच्छी तरह से ज्ञात है, एक दस्तावेज़ को इसकी पूर्णता में व्याख्या की जानी चाहिए।

12. पॉलिमर इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य[4] मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:-

"19. इस संदर्भ में, इस न्यायालय के एक श्रृंखला के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुबंध के दस्तावेज़ की व्याख्या उस प्रकार करे जैसा कि पक्षों के बीच समझा गया था। जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, बनाम चंदुमल जैन[5] मामले में, इस प्रकार टिप्पणी की गई थी:

"बीमा अनुबंध से संबंधित दस्तावेज़ों की व्याख्या करते समय, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन शब्दों की व्याख्या करे जिसमें पक्षों ने अनुबंध को व्यक्त किया है, क्योंकि यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह एक नया अनुबंध बनाए, हालांकि यह कितना भी उचित क्यों न हो, अगर पक्षों ने इसे स्वयं नहीं बनाया है।"

20. इसी तरह, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम समयनल्लुर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक[6] मामले में, इस प्रकार टिप्पणी की गई थी:

> "बीमा पालिसी की व्याख्या केवल उसमें निहित प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए और इसमें प्रकट होने वाले शब्दों को कोई कृत्रिम या खींचा हुआ अर्थ नहीं दिया जा सकता है।"

21. इसलिए, अनुबंध की शर्तों की व्याख्या बिना अनुबंध के स्वरूप को बदले कठोरता से की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पक्षों के हितों को विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है।"

13. अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदमुल जैन[7] मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से भी प्रेरणा ली है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि:-

> "अन्य पहलुओं में, बीमा के अनुबंध और किसी अन्य अनुबंध के बीच कोई अंतर नहीं होता है, सिवाय इसके कि बीमा के अनुबंध में उच्चतम विश्वास यानी बीमाधारक की ओर से अच्छी पालिसी की आवश्यकता होती है और अनुबंध को आम तौर पर 'कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटेम' यानी अस्पष्टता या संदेह की स्थिति में कंपनी के विरुद्ध व्याख्या की जाने की संभावना होती है। अनुबंध तब बनता है जब प्रस्ताव का बिना किसी योग्यता के स्वीकार किया जाता है। स्वीकार करना लिखित रूप में हो सकता है या यहां तक कि परिकल्पित भी हो सकता है यदि बीमाकर्ता प्रीमियम स्वीकार करता है और उसे अपने पास रखता है। बीमाधारक के मामले में, उसकी ओर से एक सकारात्मक कार्य जिसके द्वारा वह पालिसी को मान्यता देता है या उसे लागू करने की मांग करता है, उसे इसकी पुष्टि माना जाता है। इस स्थिति को बीमाधारक

ने स्वयं स्पष्ट रूप से पहचाना था, क्योंकि उसने कवर नोट की अवधि के समाप्त होने के निकट लिखा था कि या तो उस अवधि के समाप्त होने से पहले उसे एक पालिसी जारी की जाए या कवर नोट को समय में विस्तारित किया जाए। बीमा अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करते समय, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन शब्दों की व्याख्या करे जिसमें पक्षों ने अनुबंध को व्यक्त किया है, क्योंकि यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह एक नया अनुबंध बनाए, भले ही वह कितना भी उचित क्यों न हो, अगर पक्षों ने इसे स्वयं नहीं बनाया है। प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र और कवर नोट्स को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आग और बाढ़, चक्रवात आदि को कवर करने वाली मानक पालिसी के तहत एक बीमा अनुबंध अस्तित्व में आया था।"

14. अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ वकील श्री गुप्ता ने हमारा ध्यान बज (रन ऑफ) लिमिटेड बनाम डरहम और अन्य[8] मामले की ओर आकर्षित किया है, जिसमें संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने बीमा अनुबंध की व्याख्या करते हुए अभिमत व्यक्त किया है:

"इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि एकल शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए और बीमा अनुबंधों को अधिक व्यापक रूप से देखा जाए। जैसा कि लॉर्ड मस्टिल ने चार्टर रीइंश्योरेंस कं. लिमिटेड बनाम फगन[9] में उल्लेख किया है, ऐसे सभी शब्दों को 'पूरे उपकरण के परिदृश्य में रखा जाना चाहिए' पृष्ठ 381 पर, उनके अर्थ के लिए कोई भी 'सहज प्रतिक्रिया' 'अनुबंध के अन्य नियमों का अध्ययन करके और लेन-देन के तथ्यात्मक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में रखकर' सत्यापित की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में बीमा के व्यावसायिक

पृष्ठभूमि के रूप में क्या माना जाता है और उसे अर्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है, इस पर काफी तर्क-वितर्क हुआ है, जो उनके अर्थ को आकार दे सकता है। लेकिन मेरी राय में, प्रत्येक बीमा के दायरे, उद्देश्य और उचित व्याख्या की गहन समझ उसकी भाषा के अध्ययन से प्राप्त की जा सकती है, जिसे इसकी संपूर्णता में पढ़ा जाता है। इसलिए, फिलहाल, मैं उस संबंध में प्राप्त सहायता पर ध्यान केंद्रित करता हूं।"

15. श्री गुप्ता द्वारा अपने द्वारा बताए गए द्रष्टांतों पर निर्भर करते हुए, उनका तर्क है कि पक्षों के बीच की पालिसी को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और पालिसी की पूर्णता में पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि चाहे पालिसी के तहत संरक्षित हो या न हो, सभी खेपों की घोषणा अनिवार्य नहीं है और केवल उन खेपों की घोषणा की आवश्यकता है जिनके लिए दावे दर्ज किए गए हैं। एक वैकल्पिक तर्क के रूप में, उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि प्रतिवादी-निगम ने 26.1.2000 के पत्र द्वारा अपीलार्थी के क्रेडिट बैलेंस से दो अघोषित खेपों के लिए प्रीमियम की कटौती की है, और इसलिए, प्रतिवादी-निगम ने स्वयं अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दो खेपों को भेजने की कार्रवाई को मान्यता दी है और इन परिस्थितियों में, यह उसके हिस्से पर उचित नहीं था कि वह उक्त खेपों की गैर-घोषणा के आधार पर अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दे। अनुमोदन की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए, उन्होंने हमें राजस्थान के उच्च न्यायालय बनाम पी.पी. सिंह[10], मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम सेशराव बलवंत राव चव्हाण[11] और बाबू वर्गीस बनाम केरल बार काउंसिल[12] के प्राधिकरणों की ओर संकेत किया है। हमें लगता है कि श्री गुप्ता के इस प्रस्तुति को पालिसी के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय विचार किया जाना उचित है।

16. दावे के खंडन की आलोचना करते हुए, श्री गुप्ता ने हमारा ध्यान संचार के अनुच्छेद 3 की ओर आकर्षित किया है जो कहता है कि बिल को खरीददार के देश में नोटेड और प्रोटेस्टेड नहीं किया गया था और इस संबंध में तर्क दिया है कि उक्त कारण का आरोपण पालिसी की शर्तों और प्रावधानों से परे है, क्योंकि पालिसी में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि बीमाधारक को पालिसी के तहत राशि का दावा करने के लिए खरीददार के देश में बिल को नोटेड और प्रोटेस्टेड करवाना होगा। उनका तर्क है कि पालिसी की शर्तों की कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें से कुछ भी जोड़ना या घटाना स्वीकार्य नहीं है। उक्त स्थिति को साबित करने के लिए, उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन[13] लाल पर भरोसा किया है।

17. उपरोक्त प्राधिकरण, जो मूल रूप से पालिसी पर रखी जाने वाली व्याख्या से संबंधित घोषणाएं हैं, हम पालिसी की शर्तों और प्रावधानों से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि श्री भरत संगल, प्रतिवादी-निगम के लिए विद्वान वकील ने मूल रूप से यह तर्क दिया है कि पालिसी की शर्तों और प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है और पालिसी में अनुच्छेदों को उनके रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उनमें से किसी में भी कोई अस्पष्टता नहीं है। व्याख्या के संबंध में, उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोनी चेरियन[14] मामले पर भरोसा किया है, जिसमें इस प्रकार निर्धारित किया गया है:-

> "बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच की बीमा पालिसी दो पक्षों के बीच का अनुबंध प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि बीमाकर्ता बीमाधारक द्वारा बीमा पालिसी द्वारा संरक्षित जोखिमों के कारण हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उठाता है, इसलिए समझौते की शर्तों की कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि बीमाकर्ता की दायित्व

सीमा का निर्धारण किया जा सके। बीमाधारक बीमा पालिसी द्वारा संरक्षित से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता। इसलिए, बीमाधारक को भी पालिसी में स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनी सीमाओं या शर्तों के अनुसार सख्ती से काम करना चाहिए।"

18. उपरोक्त प्राधिकरण के अलावा, उन्होंने हमें आयोग के दो निर्णयों की ओर भी संकेत किया है जहां दावे को अस्वीकार कर दिया गया था और उन्होंने ऐसा करने का साहस किया है क्योंकि इनमें से एक आदेश को इस न्यायालय में सिविल अपील संख्या 8052 के 2004 में चुनौती दी गई थी, और इस न्यायालय ने अपील को प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया था।

19. वर्तमान में पालिसी की मूल संरचना पर, प्रारंभ में यह कहना आवश्यक है कि हम, उचित समय में, पालिसी के अनुच्छेदों को विस्तार से संदर्भित करेंगे जैसा कि दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने उल्लेख किया है, लेकिन इससे पहले पालिसी की रूपरेखा का संकेत देना उपयुक्त है। पालिसी का प्रारंभिक भाग बीमित जोखिमों और उससे जुड़े प्रावधान का उल्लेख करता है। पालिसी के अनुच्छेद 2 से, जैसा कि स्पष्ट है, बीमाधारक को पालिसी के जारी होने की तारीख पर और पालिसी के संचालन के दौरान हर समय बीमाधारक के जोखिमों को प्रभावित करने वाले तथ्यों का खुलासा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 3 खेपों के संरक्षण और अपवादों से संबंधित है। उक्त संरक्षण पालिसी की शर्तों और प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 5 उन खेपों से संबंधित है जो संरक्षित नहीं हैं और इसमें जहाजीकरण की तारीख से 180 दिनों से अधिक समय के लिए खरीददार को बीमाधारक द्वारा उधार देने की अनुमति शामिल है। अनुच्छेद 7, बीमाधारक को निगम को किसी भी ऐसी घटना की सूचना देने की आवश्यकता करता है जो अधिकतम 30 दिनों के भीतर नुकसान का कारण बन सकती है। अनुच्छेद 8(अ) जहाजीकरण के संबंध में घोषणा देने की आवश्यकता करता है। अनुच्छेद 14B(ब)

बताता है कि जिन मालों की डिलीवरी नहीं हुई है, वे बीमाधारक की संपत्ति बने रहते हैं और बीमाधारक द्वारा किए गए किसी भी पुनः विक्रय को निगम की पूर्व स्वीकृति के साथ होना चाहिए। अनुच्छेद 19 जो दायित्व से छूट के संबंध में है, उप-अनुच्छेद (अ) में यह निर्धारित करता है कि यदि बीमाधारक ने बिना किसी चूक के, पालिसी के अनुच्छेद 8(अ) के अनुसार घोषित करने के लिए आवश्यक सभी खेपों की घोषणा नहीं की है और अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है, तो बीमाकर्ता दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि निगम द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न दी जाए। अनुच्छेद 28 शर्तों के पालन के लिए प्रदान करता है जो विशेष रूप से यह बताता है कि पालिसी या घोषणा या प्रस्ताव या घोषणा में निहित प्रत्येक शर्त और प्रावधान का उचित प्रदर्शन और पालन निगम पर दायित्व थोपने की पूर्व शर्त होगा। अनुच्छेद 29 शर्तों का पालन न करने से संबंधित है। यह कहता है कि बीमाधारक द्वारा पालिसी की शर्तों और प्रावधानों का पालन न करने को निगम द्वारा माफ किया गया, उचित ठहराया गया या स्वीकृत माना जाएगा, जब तक कि निगम द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट अनुमोदन नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 30 संरक्षित नहीं होने वाले जोखिमों से संबंधित है और यह बताता है कि यदि किसी भी घोषित खेप के संबंध में कोई खाता या बिल पालिसी के तहत प्रदान की गई सीमाओं से अधिक होता है, तो निगम की घोषणा की कोई भी मान्यता, बीमाधारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान या प्रस्तुति, निगम को दायित्व उठाने के लिए बाध्य माना जाएगा। ये पालिसी के मूल तत्व हैं।

20. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने पालिसी के अनुच्छेद 3, 7, 8, 19, 27, 28 और 29 का उल्लंघन किया है। हमारे द्वारा पहले उल्लेखित प्राधिकरणों पर निर्भर करते हुए, यदि अनुच्छेद 2 और 10 को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रीमियम केवल उन खेपों के लिए देय है जिन पर

पालिसी लागू होती है।अपीलार्थी ने अपने जोखिम पर दो खेपें भेजीं क्योंकि क्रेडिट सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और उक्त खेपों के लिए अपीलार्थी ने कोई आवरण नहीं मांगा था। इस पृष्ठभूमि में, श्री गुप्ता, अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुति है कि पालिसी उन दो खेपों को कवर नहीं करती है और इसलिए, अपीलार्थी के लिए प्रतिवादी-निगम को उन्हें घोषित करने की कोई बाध्यता नहीं थी। अनुच्छेद 8(अ) का संदर्भ देते हुए, उनका तर्क है कि वहां प्रयुक्त शब्द अर्थात 'सभी खेपें' को अनुच्छेद 10 की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए और अनुच्छेद 10 में 'संबंधित घोषणा' शब्द का उपयोग होता है, इसलिए केवल संबंधित घोषणाएं ही की जानी चाहिए। प्रीमियम की अवधारणा का उल्लेख करते हुए, श्री गुप्ता का कहना है कि देय प्रीमियम सकल चालान मूल्य पर है और उन सभी खेपों पर है जिन पर पालिसी लागू होती है और उक्त प्रीमियम पालिसी के अनुच्छेद 8(अ) के अनुसार खेप की संबंधित घोषणा प्रस्तुत करते समय निगम को देय है और इसलिए, अनुच्छेद 10 के तहत किया जाने वाला भुगतान उन सभी खेपों के सकल चालान मूल्य से संबंधित है जिन पर पालिसी लागू होती है और अनुच्छेद 8(अ) के तहत की जाने वाली घोषणा भी उससे संबंधित है।

21. उन्होंने जो एक अन्य पहलू उजागर किया है वह यह है कि आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी ने मालों को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और ऋण संग्रह एजेंसी को कोई संचार नहीं किया है। तर्क दिया जाता है कि पालिसी की शर्तों के तहत ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है और वास्तव में, अपीलार्थी ने 11.1.2000 के पत्र द्वारा निगम द्वारा सुझाए गए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। किसी भी मामले में, पालिसी के अनुच्छेद 23 के अनुसार, यह प्रस्तावना है कि प्रतिवादी-निगम को पालिसी के तहत देय राशि का भुगतान अपीलार्थी को करना है और ऐसी राशि के भुगतान के बाद ही, निगम बीमाधारक से अनुच्छेद में निर्धारित कदम उठाने के लिए कह सकता है और इसलिए, आयोग द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष

पूरी तरह से भ्रामक है। ऋण संग्रह एजेंसी को लिखने के संबंध में, वरिष्ठ वकील ने आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की गंभीर रूप से आलोचना की है क्योंकि यह दिखाने वाले दस्तावेज़ हैं कि उसने निगम द्वारा दिए गए पते के अनुसार संचार किया था और बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता को यह संचार किया गया था कि पता गलत था और उसके द्वारा भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र वापस आ गया था। सही पते पर भेजा गया अनुरोध अनुत्तरित रहा।

22. पहले, हम अनुच्छेद 5 से निपटेंगे जो संरक्षित नहीं होने वाली खेपों से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "5. संरक्षित नहीं होने वाली खेपें। निगम की लिखित स्वीकृति के बिना (जो कि निगम को देने के लिए बाध्य नहीं है), यह पालिसी किसी भी ऐसी खेप पर लागू नहीं होगी जो:'
>
> (ए) किसी अनुबंध या बिक्री समझौते के तहत की गई है जिसमें बेची गई या बेचने के लिए सहमत होने वाली वस्तुओं की प्रकृति, मात्रा और मूल्य, भुगतान की नियत तारीख और भुगतान किए जाने वाले मुद्रा का उल्लेख नहीं होता है;
>
> (बी) किसी ऐसे खरीददार को चालानित की गई है जिसकी मुद्रा भारत में वर्तमान में प्रभावी विनिमय नियंत्रण कानूनों, नियमों और/या विनियमों द्वारा अनुमति नहीं है;
>
> (सी) बीमाधारक द्वारा खरीददार को जहाजीकरण की तारीख से 180 दिनों से अधिक समय के लिए उधार देने को शामिल करता है, जब तक कि निगम द्वारा लिखित रूप में विपरीत सहमति नहीं दी गई हो।"

23. पालिसी के अनुच्छेद 5(सी) के अनुसार, जैसा कि हम पाते हैं, बीमाधारक द्वारा खरीददार को उधार देने की अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि निगम द्वारा लिखित रूप में विपरीत सहमति नहीं दी गई हो। 2.9.1999 के पत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने नौ नारिवाहन के 90 दिनों के भीतर भुगतान की शर्तों को दिखाया है। अपीलार्थी ने 60 दिनों का उधार दिया था जो 90 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर है। यदि अनुच्छेद 5(सी) को ठीक से समझा जाए, तो प्राप्त तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में हम राज्य आयोग और आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं हो सकते हैं कि भुगतान की अवधि को कम करने के संबंध में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जो निर्धारित है वह यह है कि यदि बीमाधारक 180 दिनों से अधिक समय के लिए उधार देता है, तो निगम दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। यह बाहरी सीमा है और चूंकि बीमाधारक ने उक्त अवधि के भीतर ऋण निर्धारित किया है, इसलिए उसे उसके खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।

24. दूसरा उल्लंघन संबंधित है लदान की घोषणाओं में से 50% संख्या और 30% मूल्य की अघोषित रहने के साथ। निगम ने इस चूक को गंभीर और अक्षम्य माना है, जो कि पालिसी की धाराओं 1, 2, 7(अ), 8(अ), 10, 19(अ), 28, और 29 का उल्लंघन करती है। इस विवाद को उचित तरीके से समझने के लिए, हम नीचे उल्लिखित धाराओं को यहाँ पुनः प्रस्तुत करते हैं:-

> "1. प्रस्ताव और घोषणा: इस पॉलिसी का आधार प्रस्ताव और उसमें की गई घोषणा होगी और यह इसका हिस्सा बनेगी और यदि प्रस्ताव या घोषणा में निहित कोई भी कथन असत्य या किसी भी प्रकार से गलत होता है, तो यह पॉलिसी निरर्थक हो जाएगी लेकिन निगम किसी भी प्रीमियम को रख सकता है जो कि अदा किया गया है।

2. तथ्यों का प्रकटीकरण: किसी भी कानूनी नियम के प्रतिकूल होने के बिना यह घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी को इस शर्त पर दिया जाता है कि बीमाकृत ने इस पॉलिसी के जारी होने की तारीख पर सभी तथ्यों का प्रकटीकरण किया है और इस पॉलिसी के संचालन के दौरान हमेशा समय पर सभी ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करेगा जो किसी भी तरीके से बीमित जोखिमों को प्रभावित करते हैं।"

xxx xxx xxx

7. बीमाकृत के दायित्व: बीमाकृत को निम्नलिखित करना चाहिए:

(अ) सभी उचित और सामान्य देखभाल, कौशल और पूर्वसोच का उपयोग करना और हानि को रोकने या कम करने के लिए सभी संभव उपायों को अपनाना, जिसमें निगम द्वारा आवश्यक कोई भी उपाय शामिल हो सकता है (यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्यवाही का संस्थापन भी)।

8. घोषणाएँ:

(अ) लदानों की घोषणा: प्रत्येक कैलेंडर माह के 15 वें दिन या उससे पहले, बीमाकृत को निगम के निर्धारित प्रपत्र में, पिछले महीने के दौरान उसके द्वारा किए गए सभी लदानों की घोषणा, निगम को प्रदान करनी चाहिए। यदि किसी महीने में कोई लदान नहीं किया गया है, तो भी 'शून्य' घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

xxx xxx xxx

10. प्रीमियम की आवृत्ति और अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान: बीमाकृत को इस पॉलिसी के अनुसार सभी लदानों के सकल चालान

मूल्य पर, अनुसूची-II में निर्दिष्ट दरों पर, या जैसा कि मामला हो, समय-समय पर लागू अन्य दरों पर, प्रीमियम का भुगतान करना होगा और इस तरह के लदान के निर्माण पर तत्काल प्रीमियम देना होगा और इस पॉलिसी की धारा 8(अ) के अनुसार लदानों की संबंधित घोषणा प्रस्तुत करते समय न्यूनतम प्रीमियम के संदर्भ में किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि देय और भुगतान योग्य हो सकता है।

xxx xxx xxx

19. दायित्व से अस्वीकृति: इस पॉलिसी में निहित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, जब तक कि निगम द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हो, निगम की किसी भी लदान या उसके किसी भाग के सकल चालान मूल्य के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा, यदि:

(अ) बीमाकृत ने इस पॉलिसी की धारा 8(अ) के अनुसार घोषित किए जाने वाले सभी लदानों को बिना किसी चूक के घोषित नहीं किया है और इस पॉलिसी की धारा 10 के अनुसार प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।

28. शर्तों का पालन: यहाँ या प्रस्ताव या घोषणा में निहित प्रत्येक शर्त और प्रावधान का उचित प्रदर्शन और पालन, निगम द्वारा यहाँ उत्पन्न किसी भी दायित्व और बीमाकृत द्वारा इसके प्रवर्तन के लिए एक पूर्वशर्त होगा।

29. शर्तों का पालन न करना: बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्तों और प्रावधानों का पालन न किए जाने को निगम द्वारा माफ, अनुमोदित या

स्वीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वही स्पष्ट रूप से निगम द्वारा लिखित में माफ, अनुमोदित या स्वीकार नहीं की जाती है, और ऐसी माफी, अनुमोदन या स्वीकृति निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों और प्रावधानों के अधीन होगी, जिसमें इस पॉलिसी की धारा 30 के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत में कमी शामिल हो सकती है, जो कि निगम द्वारा देय हानि का प्रतिशत होता है।"

25. जैसा कि संविधान पीठ द्वारा चंदमुल जैन (सुप्रा) मामले में निर्णय दिया गया है, बीमा के अनुबंध में बीमाकृत की ओर से अच्छी निष्ठा की आवश्यकता होती है और यदि कोई अस्पष्टता हो, तो इसे कंपनी के विरुद्ध निर्मित किया जाना चाहिए। अन्य प्राधिकरणों के अनुसार, बीमा पॉलिसी को सख्ती से निर्मित किया जाना चाहिए और इसे पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि पॉलिमर इंडिया (पी) लिमिटेड (सुप्रा) मामले में निर्णय दिया गया है, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दस्तावेज़ की व्याख्या करे जैसा कि पक्षों के बीच समझा जाता है और इसमें निहित शर्तों के संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है।

26. उपरोक्त कानूनी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, हमें उस स्कोर पर अस्वीकृति से संबंधित पॉलिसी में निहित नियमों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। धारा 8(अ) जो घोषणाओं से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। उक्त धारा आवश्यक करती है कि प्रत्येक कैलेंडर माह के 15 वें दिन से पहले, बीमाकृत को निगम को पिछले महीने के दौरान किए गए लदानों की निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रदान करनी चाहिए और यदि किसी महीने में कोई लदान नहीं हुआ है, तो भी 'शून्य' घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। धारा 9 न्यूनतम प्रीमियम से संबंधित है और धारा 10 प्रीमियम की आवृत्ति और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से संबंधित है। धारा 19(अ), जैसा कि पहले बताया गया है, दायित्व से अस्वीकृति से संबंधित है। धारा 19, अस्वीकृति की धारा, स्पष्ट रूप

से बताती है कि जब तक निगम द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, निगम किसी भी लदान या उसके किसी भाग के सकल चालान मूल्य के संबंध में कोई दायित्व नहीं रखेगा यदि बीमाकृत ने धारा 8(अ) की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी लदानों की घोषणा बिना किसी चूक के नहीं की है और धारा 10 के अनुसार प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है। श्री संग जी का कहना है कि ये धाराएँ बीमाकृत पर बाध्यकारी हैं और वह अपनी इच्छानुसार इन आवश्यकताओं के साथ खेल नहीं सकता। श्री गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ने तर्क दिया है कि इन धाराओं को धाराओं 2, 10 और 30 के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और इस तरह से पढ़ी जाए, तो ये धाराएँ नहीं कहती हैं कि सभी लदानों की घोषणा की जानी चाहिए। पस्तुतिकरण को समझने के लिए, हमें उचित लगता है कि धाराएँ 2, 10, और 30 को यहाँ पुनः प्रस्तुत करें:-

> "2. तथ्यों का प्रकटीकरण: किसी भी कानूनी नियम के प्रतिकूल होने के बिना यह घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी को इस शर्त पर दिया जाता है कि बीमाकृत ने इस पॉलिसी के जारी होने की तारीख पर सभी तथ्यों का प्रकटीकरण किया है और इस पॉलिसी के संचालन के दौरान हमेशा समय पर सभी ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करेगा जो किसी भी तरीके से बीमित जोखिमों को प्रभावित करते हैं।
>
> XXX XXX XXX
>
> 10. प्रीमियम की आवृत्ति और अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान: बीमाकृत को प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो इस पॉलिसी में अनुसूची-II के अनुसार निर्धारित दरों पर, या जैसा कि मामला हो, वर्तमान में लागू अन्य दरों पर, इस पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले सभी लदानों के सकल चालान मूल्य पर, ऐसे लदान के निर्माण पर

तत्काल किया जाना होगा और इस पॉलिसी की धारा 8(अ) के अनुसार लदानों की संबंधित घोषणा प्रस्तुत करते समय न्यूनतम प्रीमियम के समायोजन के बाद देय और भुगतान योग्य किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान निगम को करना होगा।

XXX XXX XXX

30. अनावृत्त जोखिम: यदि किसी खाते या बिल (या उसके किसी विस्तार या नवीकरण) के संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा यहाँ दी गई सीमाओं से अधिक होती है या अन्यथा पॉलिसी के अनुसार नहीं होती है, तो निगम द्वारा घोषणा की स्वीकृति और बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान या प्रस्ताव निगम को ऐसे खाते या बिल (या उसके नवीकरण या विस्तार) के संबंध में दायित्व उठाने के लिए बाध्य नहीं माना जाएगा।"

27. श्री गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने उन शब्दों पर अत्यधिक जोर दिया है कि बीमित को "सभी तथ्यों का खुलासा करना चाहिए" जो किसी भी प्रकार से बीमित जोखिमों को प्रभावित करते हैं। इसी तरह, उन्होंने धारा 10 में आने वाले "इस पॉलिसी के अनुसार सभी शिपमेंट्स के सकल इनवॉइस मूल्य पर" शब्दों पर भी जोर दिया है। धारा 30, जैसा कि श्री गुप्ता कहेंगे, अनावृत्त जोखिमों से संबंधित है जो पॉलिसी के अनुसार नहीं हैं। उनका यह कहना है कि अनावृत्त जोखिमों के संबंध में प्रीमियम का भुगतान निगम को दायित्व उठाने के लिए बाध्य नहीं करता। श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क, प्रथम दृष्टया बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन अधिक सूक्ष्म अवलोकन पर इसे महत्वहीनता में विलीन हो जाना चाहिए। पॉलिसी की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कानूनी सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं है कि अस्पष्टता की स्थिति में, निर्माण बीमित के पक्ष में किया जाना चाहिए। धाराएँ

B(ए) और 19(ए) क्रमशः घोषणाओं और दायित्व की अस्वीकृति से संबंधित हैं। ये पूरी तरह से विशिष्ट हैं। धारा 2 तथ्यों के खुलासे से संबंधित है। धारा 10 प्रीमियम की परिस्थितियों और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से संबंधित है और धारा 30 अनावृत्त जोखिमों से। धारा 18(ए) और 19(बी), जिन्हें हमने यहाँ उल्लेखित किया है, पूरी तरह से स्पष्ट हैं और उनमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार बीमित पर पॉलिसी के तहत एक दायित्व डाला गया है। पॉलिसी के अनुसार, उसे प्रत्येक कैलेंडर माह के 151वें दिन या उससे पहले निगम को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होती है जिसमें पिछले माह के दौरान किए गए सभी शिपमेंट्स का विवरण होता है और यहां तक कि अगर कोई नौ परिवहन नहीं किया गया है तो भी उसे 'शून्य' घोषणा देनी होती है। धारा 19(ए) धारा 18(ए) की शर्तों के अनुसार घोषणा का उल्लेख करती है। इसमें "कोई चूक नहीं" शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसमें धारा 10 के अनुसार प्रीमियम के भुगतान से संबंधित एक और पोस्ट्युलेट जोड़ा गया है। धारा 19(ए) में दी गई दोहरी आवश्यकताएं संचयी हैं। इन्हें अलग-थलग पढ़ा नहीं जा सकता। बीमित को धारा 8(ए) के अनुसार बिना किसी चूक के शिपमेंट्स की घोषणा करनी होती है और साथ ही धारा 10 के अनुसार प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। केवल प्रीमियम का भुगतान करने से निगम नुकसान की प्रतिपूर्ति करने या उस पर दायित्व लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता। दावे को बनाए रखने के लिए बीमित द्वारा घोषणा के संबंध में अनुपालन करने का प्रदर्शन करना भी आवश्यक है। धारा B(a) का यह निर्माण कि बीमित के पास यह विकल्प है कि वह कौन से नौ परिवहन को कवर करेगा और किन्हें छोड़ देगा, पॉलिसी के आदेश के विरुद्ध जाएगा। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये विशिष्ट धाराएँ बीमित के दायित्वों से संबंधित हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रीमियम के भुगतान और इस क्षेत्र में कवर किए गए जोखिम की अवधारणा को जोड़ने का प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। सामान्य धाराएँ मूल रूप से यह बताती हैं कि कौन से जोखिम कवर किए जाते हैं और

कौन से नहीं, प्रीमियम की गणना और भुगतान कैसे किया जाना चाहिए। अंततः जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि जहाँ बीमाकर्ता की दायित्व से विशेष रूप से छूट होती है, उन धाराओं के पॉलिसी में बिल्कुल स्पष्ट, निर्विवाद और अस्पष्टता रहित होते हैं। वाणिज्यिक लेन-देन में एक पॉलिसी प्राप्त करने के बाद बीमित को पॉलिसी को पूरी तरह समझना चाहिए। पॉलिसी का समग्र और सामंजस्यपूर्ण रूप से निर्माण इस बात के लिए कोई संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि बीमित-अपीलार्थी के पक्ष में व्याख्या की मांग करने वाली कोई अस्पष्टता या द्विअर्थी स्थिति नहीं है। चाहे जो भी कारण अपीलार्थी दे, उसने धारा 8(ए) के अनुसार घोषणा नहीं की है, जिसे धारा 19(ए), बहिस्कारी धारा में फिर से संदर्भित किया गया है।ऐसे बीमा अनुबंध की व्याख्या की अवधारणा के लिए यह एक विपरीत होगा, यदि बीमाकर्ता पर दायित्व लागू किया जाता है। आयोग का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने माल को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाए थे, वर्तमान उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यद्यपि यह निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष, त्रुटिपूर्ण है, जो हमारे स्वतंत्र विश्लेषण पर आधारित है, सही है।

28. मामले से निपटते समय हमें एक और पहलू पर ध्यान देना चाहिए जिसे श्री गुप्ता ने एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य[15] मामले के निर्णय का हवाला देते हुए उजागर किया है। उक्त मामले में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो राज्य की एक साधन है, ने दावाकर्ता के दावे को अस्वीकृत किया था जिसके विरुद्ध एक रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के सीखे हुए सिंगल जज के समक्ष अस्वीकरण को निरस्त करने के लिए दायर की गई थी। सीखे हुए सिंगल जज ने पक्षों की सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकाला कि पक्षों के बीच विवाद बीमा के अनुबंध से उत्पन्न हुआ था और पहला उत्तरदाता अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए एक राज्य होने के नाते अनुबंध की शर्तों से बंधा था और तदनुसार उन्होंने रिट याचिका को मंजूर

किया। इंट्रा-कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच ने राय व्यक्त की कि रिट याचिकाकर्ता के दावे में विवादित तथ्यों के प्रश्न शामिल थे और इसलिए, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट प्रक्रिया में निर्णीत नहीं किया जा सकता था। हालांकि, यह आगे बढ़कर यह कहा कि सीखे हुए सिंगल जज ने कानून को गलत तरीके से लागू किया था और आगे यह निष्कर्ष निकाला कि बीमित ने अनुबंध की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया था। इस न्यायालय ने रिट याचिका की अनुपालनीयता के संबंध में कई निर्णयों का संदर्भ लिया और यह विचार व्यक्त किया कि केवल इसलिए कि मुकदमेबाजी के पक्षों में से एक पक्ष मामले के तथ्यों के संबंध में विवाद उठाता है, ऐसी याचिका सुनने वाली न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमेशा पक्षों को एक मुकदमे में ले जाने के लिए बाध्य नहीं होती है। इस तरह निष्कर्ष निकालते हुए न्यायालय ने राय व्यक्त की कि एक बार जब राज्य या उसकी साधन अनुबंध का पक्ष होती है, तो उस पर कानून के अनुसार न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत रूप से कार्य करने का दायित्व होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता है, और इसलिए, राज्य की साधन होने के नाते, निगम ने अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं के विरुद्ध कार्य किया, और इसलिए, रिट न्यायालय स्वेच्छाचारी कार्य को निष्प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। न्यायालय ने बीमा के अनुबंध की संबंधित धाराओं का स्वीकार किए गए तथ्यों के पृष्ठभूमि में उल्लेख किया। बीमित और बीमाकर्ता के बीच बीमा का अनुबंध मुख्य रूप से निर्यातक और कजाक कॉर्पोरेशन के बीच अनुबंध पर आधारित था। चाय के निर्यात के भुगतान से संबंधित प्रासंगिक धारा धारा 6 में शामिल की गई थी। उक्त धारा को उसी दिन संशोधित किया गया था जब अनुबंध निर्यातक और कजाक कॉर्पोरेशन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, एक परिशिष्ट द्वारा। न्यायालय ने राय व्यक्त की कि उपलब्ध तथ्यों में परिशिष्ट अनुबंध की मूल धारा 6 का एक अभिन्न भाग बन गया था। न्यायालय ने आगे अनुबंध में धाराओं से निपटने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई

और निर्धारित किया कि धारा 6 के अनुसार विचारणीयता के भुगतान के वैकल्पिक तरीके स्वीकार्य थे। उस संदर्भ में न्यायालय ने आगे राय व्यक्त की:

> "बीमा अनुबंध की शर्तें जिन पर पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी, वे निर्यातक और आयातक के बीच किए गए अनुबंध की शर्तों के बाद थीं जिनमें परिशिष्ट शामिल था, इसलिए, बिना हिचकिचाहट के हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि पहले उत्तरदाता ने बीमा पॉलिसी जारी की थी, यह जानते हुए कि विचारणीयता के भुगतान के अधिक से अधिक एक तरीके थे और उसने विचारणीयता के भुगतान के सभी तरीकों की असफलता का बीमा किया था। पत्राचार से और बीमा पॉलिसी की शर्तों से, यह देखा गया है कि पहले उत्तरदाता निगम को बीमित जोखिम के लिए भुगतान करने के लिए दोषी बनाने के लिए केवल दो शर्तों की मौजूदगी को पूर्व शर्त के रूप में बनाया गया है, जो है: (i) कजाक कॉर्पोरेशन द्वारा प्राप्त किए गए माल के लिए भुगतान में चूक होनी चाहिए; और (ii) कजाखस्तान सरकार द्वारा उनकी गारंटी पूरी करने में विफलता होनी चाहिए।"

ऐसा कहने के बाद न्यायालय ने यह नियमित किया कि बीमित द्वारा अनुबंध की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। राहत प्रदान करने के संदर्भ में न्यायालय ने कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[16] मामले में निर्णय का उल्लेख किया और इस प्रकार निर्णय दिया:-

> "53. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जब राज्य की एक साधन जनहित और जन कल्याण के विरुद्ध, अन्यायपूर्ण, अनुचित और अतार्किक रूप से अपने संवैधानिक, सांविधिक या अनुबंधिक दायित्वों में कार्य करती है, तो वास्तव में वह संविधान के अनुच्छेद 14 में पाए जाने वाले

संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध कार्य करती है। इसलिए यदि हम इस मामले के तथ्यों पर अनुच्छेद 14 की प्रासंगिकता के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला उत्तरदाता राज्य की एक साधन होने के नाते और एक एकाधिकार निकाय होने के कारण, अपीलार्थीओं को अपने निर्यात जोखिम को कवर करने के लिए विवशता से संपर्क करना पड़ा। अपीलार्थीओं के जोखिम को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी को पहले उत्तरदाता द्वारा सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद और 16 लाख रुपये से अधिक की विशाल राशि के रूप में प्रीमियम प्राप्त करने के बाद जारी की गई थी। तथ्यों पर हमने पाया है कि पॉलिसी की शर्तें पहले उत्तरदाता द्वारा कवर किए गए जोखिम के संबंध में किसी भी अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं देती हैं। हम यह भी विचारशील राय रखते हैं कि पहले उत्तरदाता की पॉलिसी के तहत दायित्व तब उत्पन्न हुआ जब निर्यातक की चूक हुई और उसके बाद जब कजाखस्तान सरकार ने अपनी गारंटी पूरी करने में विफल रही। यह आरोप नहीं है कि प्रश्न में आने वाले अनुबंध धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व से प्राप्त किए गए थे। इस तरह की तथ्यात्मक स्थिति में, हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्य उच्च न्यायालय या इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने से न रोकते हैं और न ही रोकने चाहिए।"

29. श्री गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने पहले उद्धृत पैराग्राफ पर अत्यधिक जोर दिया है। हमने निर्णय का विश्लेषण किया है ताकि संदर्भ और तथ्यों की स्थिति को समझ सकें जैसा कि निर्णय में चित्रित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायालय ने निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचा था कि बीमा अनुबंध की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं

हुआ था। इसलिए, हमारी विचारशील राय में उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इस मामले में, जैसा कि पहले ही निर्धारित किया गया है; बीमा अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमें यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि उक्त निर्णय को शायद एक प्राधिकरण के रूप में उद्धृत किया गया है क्योंकि उत्तरदाता-निगम वहां भी उत्तरदाता था।

30. नतीजतन, अपील, जिसमें कोई गुण नहीं है, खारिज की जाती है। हालांकि, हम कोई लागत से सम्बन्ध में अधिनिर्णय से बचते हैं।

कल्पना के.त्रिपाठी **अपील खारिज की गई।**

1. (1996) 6 एससीसी 425

2. (1969) 2 एससीआर 430= एआईआर 1969 एससी 227

3. (2006) 13 एससीसी 737

4. (2005) 9 एससीसी 174

5. (1996) 3 एससीआर 500: एआईआर 1996 एससी 1644

6. (1999) 8 एससीसी 5432

7. (1966) 3 एससीआर 500 = एआईआर 1966 एससी 1644

8. (2012) यूकेएससी 14

9. (1997) एसी 313, 384

10. (2003) 4 एससीसी 239

11. (1989) 3 एससीसी 132

12. (1999) 3 एससीसी 422

13. (2004) 8 एससीसी 644

14. (1999) 6 एससीसी 451

15. (2004) 3 एससीसी 553

16. (1991) 1 एससीसी 212

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक नाजिश रशीद, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****